भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4267
उत्तर देने की तारीख 18 मार्च, 2026

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल टावर

4267. श्री नवसकनी के.:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर के लगभग 55,000 गांवों को 4जी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन में सुधार करने के लिए 41,331 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 41,160 मोवाइल टावरों को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) तमिलनाडु में जिला-वार ऐसे कितने मोबाइल टावरों को स्वीकृत, स्थापित और चालू किया गया है;
(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 4जी कनेक्टिविटी के लिए कितने गांवों की पहचान की गई है और अब तक कितनी प्रगति हुई है;
(घ) क्या तमिलनाडु के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विश्वसनीय मोबाइल और इंटरनेट संपर्क प्रदान करने में विलंब अथवा कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की कोई सूचना मिली है; और
(ङ) राज्य में इस कार्य को शीघ्र पूरा करने, नेटवर्क की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कवर न किए गए गांवों के निवासियों के लिए डिजिटल सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) सरकार ने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के माध्यम से देश भर के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने और डिजिटल समावेशन को बेहतर बनाने के लिए परियोजनाओं को अनुमोदन दिया है। इन परियोजनाओं में शामिल गांवों के सर्वेक्षण के बाद, सेवा से वंचित 44,802 गांवों/स्थानों को कवरेज प्रदान करने के लिए 33,422 मोबाइल टावरों की योजना बनाई गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से दिनांक 28.02.2026 तक 32,455 गांवों/स्थानों को कवर करते हुए 22,840 टावर ऑन-एयर हैं।

(ख) और (ग) तमिलनाडु सहित भारत के इस सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 4जी सेचुरेशन परियोजना को अनुमोदित किया गया है। तमिलनाडु राज्य में इस परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत मोबाइल टावरों, नियोजित गांवों, ऑन-एयर टावरों की संख्या और जिले-वार कवर किए गए गांव डीबीएन की वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है।

(घ) मोबाइल टावरों के लिए भूमि के आवंटन में देरी जैसे कारकों के कारण कुछ साइटों के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है।

(ङ) इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के साथ नियमित समीक्षा बैठकें और राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) के सेवा गुणवत्ता मानक और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा विनियम, 2024 बनाए हैं। डीबीएन मोबाइल परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सेवा गुणवत्ता के मापदंड ट्राई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हों।

****